भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या4895
दिनांक 01.04.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत का विकास

4895. श्री राहुल कस्वांः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों की व्यापक विकास के कार्यकलापों के दस्तावेजीकरण हेतु पंचायत एंटरप्राइजेज सूइट परियोजना को बंद कर दिया है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित वैकल्पिक कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;
(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस परियोजना के लिए पूर्ण आंकड़े उपलब्ध करा दिए हैं;
(घ) क्या सरकार का ग्राम पंचायतों के विकास और वैकल्पिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति बनाने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ग)जी नहीं, सरकार ने पंचायत एंटरप्राइजेज सुइट (पीईएस) परियोजना को बंद नहीं किया है। ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कामकाज के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए कोर कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एक सुइट तैयार किया गया था, जिसमें आयोजना, बजटन, कार्यान्वयन, लेखांकन, निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा और प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी करने जैसी नागरिक सेवाओं की प्रदायगी शामिल है। ये एप्लीकेशन सामूहिक रूप से पंचायत एंटरप्राइजेज सुइट (पीईएस) बनाते हैं जो वेब-आधारित होते हैं, जिससे निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।

इसके अलावा, पीआरआई में ई-गवर्नेंस को बढ़ाने और डिजिटल संचालन को कारगर बनाने के लिए, सरकार ने 24अप्रैल, 2020को ई-ग्रामस्वराज की शुरुआत की। यह कार्य-आधारित लेखांकन एप्लीकेशन ई-पंचायत एमएमपी के तहत पहले से उपलब्ध एप्लीकेशनों की कार्यक्षमताओं को एकीकृत करता है, जिसमें प्लानप्लस, एक्शनसॉफ्ट, पीआरआईएसॉफ्ट और राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका (एनएडी) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के साथ एरिया प्रोफाइलर एप्लिकेशन को भी ई-ग्रामस्वराज में शामिल किया गया है, जो पंचायत निर्देशिका के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने और अपलोड करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल का उपयोग करती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ई-ग्रामस्वराज के तहत राज्यों द्वारा की गई प्रगति **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इस पहल का उद्देश्य देश भर में पंचायतों के लिए बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और उपयोग में आसानी सुनिश्चित करते हुए शासन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

मंत्रालय ई-पंचायत एमएमपी के तहत डेटा प्रविष्टि और प्लेटफ़ॉर्म उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम कर रहा है। फीडबैक के आधार पर निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जिसमें ई-ग्रामस्वराज में कार्यक्षमता उन्नयन और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं।

हालाँकि, देश भर में पंचायतों की तत्परता के स्तर में भिन्नता के कारण, राज्य इन एप्लीकेशनों को लागू करने के अलग-अलग चरणों में हैं।

(घ) और (ङ) सरकार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाने और समग्र पंचायत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने, उनकी शासन क्षमता को बढ़ाने और डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्वामित्व योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) और ई -ग्रामस्वराज सहित कई पहलों को लागू किया जा रहा है।

सरकार एआई और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके ग्राम पंचायतों के लिए डिजिटल परिवर्तन पहल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निर्बाध वित्तीय लेनदेन के लिए ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस को मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास संबंधी पहलें की जा रही हैं।

स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करके गांवों में आबादी क्षेत्रों के सटीक भू-संदर्भित/जिओ-रेफरन्स्डमानचित्र बनाए गए हैं। एमओपीआर के ग्राम मानचित्र (https://grammanchitra.gov.in/) एप्लिकेशन में एआई टूल्स का उपयोग करके, निवासियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए गांव के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की क्षमता का अनुमान लगाया गया है।

***

अनुलग्नक-I

'ग्राम पंचायत के विकास' के संबंध में दिनांक 01.04.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4895 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतें एवं समकक्ष की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12970	660	660	642	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	222	0	0	0	27	25	8
3	असम	2662	2197	2176	191	191	189	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8045	534	534	530	38	38	38
5	छत्तीसगढ	11596	11594	11516	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	गुज	146	145	13890	248	248	248	33	33	33

	रात	56	99							
8	हरियाणा	6226	6222	5914	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3540	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4329	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5937	238	232	126	31	31	28
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22980	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27917	27894	26737	351	351	307	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	123	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9775	152	151	114	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11207	10837	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12519	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12636	572	540	508	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1185	1174	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7795	7794	7743	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57609	826	826	818	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21

कुल	**263708**	**251928**	**242864**	**8690**	**6402**	**6135**	**652**	**642**	**612**